



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 610 राँची, मंगलवार 27 कार्तिक 1936 (श०)
18 नवम्बर, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

17 नवम्बर, 2014

1. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-216/रा०, दिनांक 1 फरवरी, 2010
2. उपायुक्त, गढ़वा का पत्रांक-304/स्था०, दिनांक 7 अगस्त, 2009 एवं पत्रांक-618/स्था०, दिनांक 8 अगस्त, 2014
3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-3458, दिनांक 11 जून, 2010 एवं पत्रांक-11345, दिनांक 25 नवम्बर, 2013

संख्या-5/आरोप-1-171/2014 का.10998 --- श्री धरनीधर झा, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक -156/03, गृह जिला(मधुबनी -), के विरुद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, नगर ऊँटारी, गढ़वा के पद पर पदस्थापन अवधि से संबंधित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-216/रा०, दिनांक 1 फरवरी, 2010 के माध्यम से प्राप्त उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-304/स्था०, दिनांक 7 अगस्त, 2009 द्वारा आरोप प्रपत्र -'क' उपलब्ध कराया गया है।

प्रपत्र -'क' में इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं:-

1. ग्राम झगराखाड़ बनसानी के-12 व्यक्तियों के नाम से सीधे जमाबंदी कायम कर दी गई है, जो नियमानुसार नहीं है। इन व्यक्तियों के नाम से बगैर अंचलाधिकारी एवं अंचल निरीक्षक की अनुशंसा प्राप्त किये मात्र हलका कर्मचारी के प्रतिवेदन पर यह कहते हुए प्राप्त की गई कि संबंधित अवधि में अंचलाधिकारी पदस्थापित नहीं थे। इस मामले की जाँच श्री नन्द कुमार प्रसाद, तत्कालीन अंचल अधिकारी, नगर ऊँटारी, गढ़वा द्वारा किया गया। उनके जाँचप्रतिवेदन में उल्लेख है कि वर्णित - अवधि में अंचलाधिकारी पदस्थापित थे। साथ ही, श्री झा द्वारा झगराखाड़ विद्यालय के नाम से कायम जमाबंदी की गयी भूमि की पुनः दोहरी जमाबंदी कायम कर दी गयी है। विशेषकर प्लॉट सं0-939 की सभी आठ जमाबंदियाँ दोहरी जमाबंदी है, जिसके अभिलेख संधारण में भी निर्धारित नियमावली एवं प्रावधानों की उपेक्षा की गयी है। अनुमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा के आलोक में तत्कालीन उपायुक्त द्वारा सभी अभिलेखों द्वारा की गयी जमाबंदी को रद्द कर दिया गया है।

2. अपील वाद संख्या-32/ 2002-03 धर्मन राम, पतिरौंथी देवी में अपीलार्थी के पक्ष में - तत्कालीन उपसमाहर्ता द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 2003 को पारित आदेश को विलोपित करते हुए दिनांक-13 जनवरी, 2004 को विपक्षी के पक्ष में आदेश पारित किया गया।

3. अपील वाद सं0-09/ 2005-06-शिव साह, पतिदिनां फुलवा देवी में-क-4 मार्च, 2006 को विपक्षी के पक्ष में आदेश पारित किये, पुनः दिनांक-4 मार्च, 2006 को पूर्व आदेश को रद्द कर अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक-6 मार्च, 2006 को आदेश पारित किया गया।

जबकि लक्ष्मी प्रसाद शर्मा बनाम राज्य में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि उप समाहर्ता अपने आदेश की समीक्षा नहीं कर सकते।

4. श्री झा द्वारा लियाकत अंसारी, व मोहम्मद इदु अंसारी, वल्द ताज मोहम्मद अंसारी, ग्राम- -खारिज वाद संख्या-खरौंथी का दाखिल351/2006-07 द्वारा रकबा 4.42ए का किया गया है, जो मूलतः अंचलाधिकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है तथा उप समाहर्ता उसके प्रथम अपीलीय प्राधिकार होते हैं। इसमें आम इश्तिहार का तामिला सही ढंग से नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त खरौंथी अंचल से संबंधित नामांतरण वाद संख्या 345/2006-07, 398/2006-07 एवं 346/2006 -07 में अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन नहीं दिये जाने के बावजूद श्री झा द्वारा दाखिलखारिज की स्वीकृति दी गयी है।-

विभागीय पत्रांक-3458, दिनांक 11.06.2010 द्वारा श्री झा से उक्त आरोपों पर स्पष्टीकरण की माँग की गयी, परन्तु कई स्मार के बाद भी श्री झा द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं किया

गया। इसलिए उनके सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनः पेंशन नियमावली के नियम-139(बी) के तहत नोटिस निर्गत करते हुए विभागीय पत्रांक-9293, दिनांक 20.09.2013 द्वारा उनसे आरोपों के संबंध में अपना बचाव बयान समर्पित करने का अनुरोध किया गया। इसके अनुपालन में श्री झा के पत्रांक-67/पी0, दिनांक 05.11.2013 द्वारा अपना स्पष्टीकरण/बचाव बयान समर्पित किया गया।

विभागीय पत्रांक-11345, दिनांक 25.11.2013 द्वारा उपायुक्त, गढ़वा से श्री झा के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-618/स्था0, दिनांक 08.08.2014 द्वारा श्री झा के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया। उपायुक्त, गढ़वा का कहना है कि श्री झा का बचाव बयान तथ्य से हटकर प्रतिवेदित किया गया है, जो विचारणीय प्रतीत नहीं होता है। श्री झा पर लगाये गये आरोप अभिलेख के अनुसार उचित प्रतीत होता है।

श्री झा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण/बचाव बयान एवं उपायुक्त, गढ़वा के मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त, उपायुक्त, गढ़वा के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री झा के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित माने जाते हैं। अतः पेंशन नियमावली के नियम-139(बी) के तहत प्रमाणित आरोपों के लिए श्री झा की सेवा को असंतोषजनक मानते हुए इनके पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की कटौती पाँच वर्षों तक किये जाने की सजा उनपर अधिरोपित की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,

सरकार के उप सचिव।
